



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 95]

नई दिल्ली, सोमवार, मई 24, 2004/ज्येष्ठ 3, 1926

No. 95]

NEW DELHI, MONDAY, MAY 24, 2004/JYAISTHA 3, 1926

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

मुंबई 19 मई, 2004

सं. टीएमपी/79/2003-टीपीटी.—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 49 और 50 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतद्वारा, तृतीकोरिन पत्तन न्यास (टीपीटी) से, विद्युत प्रसारों के संबंध में उपरिख्य प्रभार की वसूली के लिए लेवी निर्धारित करने हेतु, प्राप्त प्रस्ताव को संलग्न आदेशानुसार निपटाता है।

सं. टीएमपी/79/2003-टीपीटी.

तृतीकोरिन पत्तन न्यास (टीपीटी)

आवेदक

आदेश
(मई 2004 के 4 वें दिन पारित)

यह प्रकरण विद्युत प्रसारों के संबंध में उपरिख्य की वसूली के लिए लेवी निर्धारित करने हेतु तृतीकोरिन पत्तन न्यास (टीपीटी) से प्राप्त प्रस्ताव के बारे में है।

- 2.1. टीपीटी ने अपने प्रस्ताव में निम्नलिखित मुख्य बातें प्रस्तुत की हैं :
- (i) उपभोक्ताओं / उपयोगकर्ताओं द्वारा उपयोग की गई बिजली के संबंध में प्रभार तमिलनाडु विद्युत बोर्ड (टीएनईवी) द्वारा निर्धारित प्रशुल्क के अनुसार एकत्रित किए जाते हैं।
- पीएसए एसआईसीएल के मामले में एक अलग ट्रांसफॉर्मर मौजूद है। इस प्रकार खपत प्रसारों के अलावा, अधिकतम मांग प्रभार और मीटर किराया भी पीएसए एसआईसीएल से लिए जाते हैं।

- (ii) उपभोक्ताओं को विद्युत का वितरण करते समय पत्तन अधिकतम मांग प्रमारों, वितरण के लिए प्रदत्त बुनियादी संरचना पर, वितरण क्षति और प्रचालन तथा अनुरक्षण लागत पर भारी खर्च करता है। अतएव, उपभोक्ताओं से उपरिव्यय प्रभार वसूलने का प्रस्ताव है। चूंकि, उपरिव्यय वसूल करने के लिए पत्तन द्वारा जून 2003 में आकलित दर न्यासी मंडल के सदस्यों को स्वीकार नहीं थी, उपयोगकर्ताओं द्वारा प्रयुक्त बिजली के संबंध में उपरिव्यय प्रभार के रूप में वसूले जाने के लिए लेवी की सिफारिश करने हेतु तीन सदस्यीय दल का गठन किया गया था।
- (iii) समिति द्वारा प्रस्तुत लागत गणना के अनुसार, कुल उपरिव्यय की वसूली के लिए विद्युत प्रभार का 142.77% पीएसए एसआईसीएएल से 158.09% अन्य उपयोगकर्ताओं से वसूल किया जाना है। इस संदर्भ में, उसने बताया है कि विद्युत उपरिव्यय प्रभार के रूप में सीओपीटी द्वारा 291% और जवाहर लाल नेहरू पत्तन न्यास द्वारा 20% प्रभार लगाया जाता है।
- (iv) बड़ी मात्रा में अप्रत्यक्ष लागत सम्मिलित होने को ध्यान में रखते हुए, समिति ने, तत्पश्चात्, केवल प्रत्यक्ष लागत 52.55% की दर से पत्तन उपयोगकर्ताओं से और 33.62% की दर से पीएसए एसआईसीएएल से वसूलने का प्रस्ताव किया था।
- (v) समिति के दो सदस्यों ने इस घटी दर पर भी आपत्ति की थी और लेवी की वसूली 5% की नाम मात्र की दर पर करने का सुझाव दिया था। समिति के सदस्यों ने उल्लेख किया कि उपयोगकर्ता पत्तन से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद विद्युत आपूर्ति सीधे तमिलनाडु विद्युत बोर्ड से प्राप्त करना चाहेंगे।

2.2. टीपीटी के न्यासी मंडल ने पत्तन उपयोगकर्ताओं, ठेकेदार इत्यादियों से उपरिव्यय प्रभार की वसूली के लिए तदर्थ आधार पर विद्युत बिल के 20% की दर से वसूल करने को अन्ततोगत्वा अपनी स्वीकृति दे दी। पत्तन ने यह कहा है कि प्रस्तावित लेवी की बाद में समीक्षा की जाएगी।

3.1. अपनाई गई परामर्शी प्रक्रिया के अनुसार प्रस्ताव की एक प्रति उपयोगकर्ता संगठनों को उनकी टिप्पणी के लिए भेजी गई थी।

3.2. उपरोक्त उपयोगकर्ताओं से प्राप्त टिप्पणियाँ प्रतिपूरक सूचनाओं के रूप में टीपीटी को भेजी गई थी। प्रत्युत्तर में, टीपीटी ने अपनी टिप्पणियाँ निम्नानुसार प्रस्तुत की है:-

- (i) टीपीटी के साथ किए गए पट्टा-अनुबंध के अनुसार तूतीकोरिन स्टीमर एजेन्डस एसोसिएशन (टीएसएए) को, पत्तन द्वारा समय-समय पर निर्धारित प्रशुल्क को वहन करना होगा। अपने दावे के समर्थन में अनुबंध की प्रति संलग्न की गई है।
- (ii) जहाँ तक टीएसएए की इस प्रेक्षा का संबंध है कि पत्तन ने समुचित औचित्य प्रस्तुत नहीं किया है, इसने स्पष्ट किया है कि पत्तन टीएनईबी को भुगतान किए गए प्रशुल्क के अलावा, मरम्मत और अनुरक्षण (जिसमें नियुक्त किए गए कर्मचारियों के स्थापना प्रभार भी सम्मिलित हैं) और विद्युत संस्थापनाओं के लागत अवमूल्यन पर भी व्यय करता है। इसकी वसूली सुविधाएं प्राप्त करने वाले उपयोगकर्ताओं से वसूल की जानी हैं।
- (iii) इसने प्रस्तावित लेवी के विधिक प्रावधानों को स्पष्ट करने के लिए विद्युत अधिनियम 2003 को विभिन्न धाराओं का निम्नानुसार संदर्भ दिया है:

भाग -IV- लाइसेंसिंग

खंड संख्या 13-छूट प्रदान करने की शक्ति

"समुचित सरकार की सिफारिशों पर समुचित आयोग, राष्ट्रीय नीतियों के अनुसार, खंड 5 के अधीन और जनहित में अधिसूचना द्वारा निदेश दे सकता है कि ऐसी शर्तों और पाबन्दियों के अधीन, यदि कोई हो और ऐसी अवधि या अवधियों के लिए, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जा सकती हैं, खंड 12 के प्रावधान किसी स्थानीय प्राधिकरण पंचायत संस्थान, उपयोगकर्ता एसोसिएशन, सहकारी सोसायटियों, गैर-सरकारी संगठनों या विशेषाधिकार प्राप्तों पर लागू नहीं होंगे।"

खंड सं. 41

"स्थानीय प्राधिकरण" से अभिप्राय किसी नगर पंचायत, नगरपालिका, नगर निगम, ग्राम स्तर पर गठित पंचायत, मध्यवर्ती या जिला स्तरीय निकाय या पत्तन आयुक्त या अन्य प्राधिकारी जो कानूनी तौर पर अधिकारी हो, या संघ या किसी राज्य सरकार द्वारा किसी क्षेत्र या स्थानीय कोष के नियंत्रण या प्रबंधन के लिए नियुक्त किया गया हो, से है।"

खंड सं. 184

इस अधिनियम के प्रावधान केन्द्र सरकार के रक्षा, परमाणु ऊर्जा से सम्बद्ध मंत्रालय या विभाग पर या ऐसे ही समान मंत्रालयों, विभागों या ऐसे मंत्रालयों या विभागों के नियंत्रणाधीन उपक्रमों या बोर्डों या संस्थानों पर, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाएं, लागू नहीं होंगे।"

विद्युत अधिनियम 2003 में उपरोक्त प्रावधानों के अनुसार, यह स्पष्ट है कि विद्युत के पारेषण, वितरण आदि के लिए एक अधिकृत व्यक्ति होने हेतु, लाइसेंस प्राप्त करने का प्रावधान किसी स्थानीय प्राधिकारी पर लागू नहीं होगा और "स्थानीय प्राधिकारी" शब्द की परिभाषा में अन्य निकायों के साथ-साथ पत्तन आयुक्त भी शामिल है।

- (iv) इसके अलावा, इसने अपने दावे के समर्थन में टीएनईबी के साथ विद्युत आपूर्ति के लिए हुए अनुबंध की शर्तों और निबन्धनों का भी संदर्भ दिया है। इस दस्तावेज में धारा 31.03(1) और (2) इस प्रकार हैं:-
 "परिसर का निर्माता या प्रोन्नतकर्ता को, जिसके नाम से आपूर्ति जारी है, फ्लैटों के अलग-अलग स्वामियों आदि को या पट्टेदारों को, सब-मीटर लगाकर विद्युत आपूर्ति पहुँचाने और उनसे बिना हानि-लाम के आधार पर विद्युत के उपयोग की लागत वसूलने (अर्थात् विद्युत के उपयोग के व्यय में हिस्सा बांटने) की अनुमति दी जा सकती है और इसे विद्युत आपूर्ति का अनधिकृत विस्तार या विद्युत आपूर्ति की अनधिकृत बिक्री नहीं मानी जाएगी।"
 पत्तन उपयोगकर्ताओं को विद्युत की आपूर्ति पहुँचा रहा है। इस धारा के अनुसार पत्तन विद्युत के उपयोग के लिए देय राशि के अतिरिक्त, हानि-लाम रहित आधार पर, किए गए व्यय की वसूली के लिए प्रभार एकत्रित कर सकता है।
- (v) अधिकतम मांग प्रभार लगातार बढ़ रहा है और अनुसंधान और स्थापना प्रभारों में भी भरपूर वृद्धि हो चुकी है। एचटी और एलटी के प्रशुल्क के बीच अन्तर भी कम हो गया है। इन अवयवों के अलावा पत्तन विद्युत संस्थापनाओं को मजबूत करने के लिए भी भारी पूंजी व्यय करता है। व्यय की प्रकृति जबकि समान हो सकती है, विभिन्न प्रकार के व्यय और व्यय की मात्रा वही (समान) नहीं रहते। इसलिए इस उपरिव्यय प्रभार को लागू करने का प्रस्ताव है।
- (vi) उपयोगकर्ता चाहें तो सीधे टीएनईबी से विद्युत प्राप्त कर सकते हैं।
- (vii) विद्युत अधिनियम में, वास्तव में आपूरित विद्युत के प्रभार के अलावा निर्धारित प्रभार का प्रावधान है, इसलिए पत्तन द्वारा प्रस्तुत और इस प्राधिकरण के विचारधीन प्रस्ताव व्यवस्थित है।
- (viii) पत्तन की अपनी निजी खपत के प्रबंधन का मुद्दा वर्तमान प्रस्ताव के दायरे से बाहर है।
- (ix) जबकि पत्तन विद्युत के लिए टीएनईबी को एचटी (III) (वाणिज्यिक) उपयोक्ताओं को लागू दरों पर प्रभारों का भुगतान कर रहा है, पत्तन द्वारा उपयोक्ताओं से एलटी (V) वाणिज्यिक दरों के आधार पर प्रभार लिए जाते हैं। इसके अलावा पत्तन को अधिकतम मांग प्रभार और अनुसंधान के अन्य आनुषंगिक प्रभारों की पूर्ति करनी पड़ती है। अतएव पत्तन द्वारा प्रभारित प्रशुल्क और विद्युत के लिए टीएनईबी के प्रशुल्क के बीच तुलना वृत्तिसंगत नहीं है।
- (x) पीएसए-एसआईसीएल को विद्युत-प्रभार का भुगतान टीएनईबी के प्रशुल्क के अनुसार करना है और टीएनईबी प्रशुल्क में लागत की वसूली बिना हानि लाम आधार पर करने का प्रावधान है। अतएव, पीएसए-एसआईसीएल को भी प्रस्तावित उपरिव्यय का भुगतान करना चाहिए।

4. प्रस्ताव की प्रारम्भिक जांच पड़ताल के आधार पर टीपीटी से विभिन्न बिन्दुओं पर अतिरिक्त सूचनाएँ प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था। टीपीटी ने प्रस्तावित लेवी के कानूनी प्रावधानों, जैसाकि पहले उल्लेख किया गया है, के संदर्भ से अपने स्पष्टीकरण प्रस्तुत किए हैं। इसके अतिरिक्त टीपीटी ने निम्नलिखित बातें कही हैं:

- (i) विद्युत लागत उपभोग किए गए यूनिटों के अनुसार विभिन्न उपगतिविधियों के प्रभारित की गई है और संबंधित उपरिव्यय को प्रबंधन और सामान्य प्रशासन व्यय के भाग के रूप में लिया गया है और पिछले सामान्य संशोधन प्रस्ताव के समय प्रस्तुत की गई लागत विवरणों में विभिन्न उप-गतिविधियों में समानुपातिक रूप से बंटवा दिया गया है।
- (ii) वर्तमान प्रस्ताव सामान्य संशोधन प्रस्ताव को प्रस्तुत करने के बाद का है, इसलिए, सामान्य संशोधन प्रस्ताव से इस लागत तत्व को बाहर रखने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। तात्कालिक प्रस्ताव के उपयोगकर्ताओं से कुल संग्रह 47.57 लाख रुपये आता है और सामान्य संशोधन प्रस्ताव पर इसका प्रभाव लगभग नगण्य होगा और इसलिए यह वर्तमान प्रस्ताव के लिए सम्बद्ध अवयव नहीं है।
- (iii) टीएनईबी द्वारा बिजली की प्रभारित प्रति यूनिट दर, प्रति एचटी प्रशुल्क के अनुसार रु. 5/- प्रति यूनिट है और रु. 300/- प्रति कि.वो. प्रति माह का अधिकतम मांग प्रभार तथा मीटर किराया सम्मिलित करने के बाद प्रभावी दर रु. 6.20 प्रति यूनिट आती है। किन्तु पत्तन टीएनईबी द्वारा निर्धारित एलटी प्रशुल्क (अर्थात् पहले 200 यूनिट के लिए रु. 5.30 प्रति यूनिट, 200 यूनिट से ऊपर रु. 5.80 + 5% विद्युत कर और निर्धारित प्रभार रु. 60/- एकत्रित करता है जिसमें किसी प्रकार के उपरिव्यय की वसूली नहीं है।
- (iv) इसने पुष्टि की है कि पत्तन द्वारा किए गए, पत्तन कर्मचारियों द्वारा किए गए उपयोग और पीएसए-एसआईसीएल द्वारा उपभोग पर व्यय को इस गणना से बाहर रखा गया है।

5. इस प्रकरण में एक संयुक्त सुनवाई 19 फरवरी 2004 को टीपीटी परिसर में आयोजित की गई थी। संयुक्त सुनवाई में टीपीटी और संबंधित उपयोक्ताओं ने अपने-अपने पक्ष रखे।

6.1 जैसा कि संयुक्त सुनवाई में निर्णय लिया गया था, टीपीटी से अनुरोध किया गया कि वह विद्युत अधिनियम 2003 के प्रावधानों की तुलना में प्रस्तावित उपरिव्यय लगाने के लिए पत्तन की सक्षमता पर टीपीटी द्वारा प्राप्त की गई कानूनी राय की एक प्रति भेजे और वर्ष 2003-04 (सं. अनु.) और 2004-05 (ब.अनु.) के लिए संबंधित लागत विवरणियाँ प्रस्तुत करें।

6.2 टीपीटी ने अपेक्षित लागत विवरणियाँ और प्रस्तावित उपरिव्यय लगाने के लिए पत्तन की सक्षमता पर टीपीटी द्वारा प्राप्त की गई कानूनी राय की एक प्रति भी प्रस्तुत की। टीपीटी के कानूनी सलाहकार द्वारा की गई कुछ मुख्य प्रस्ताव नीचे पुनः की जा रही हैं:

"मैं यह भी सुझाव दूंगा कि सेवा प्रभार वसूल करने के मुद्दे पर यदि आप टीएनईबी प्राधिकारियों की भी राय ले लें तो बेहतर होगा। मेरा अनुमान है कि विद्युत अधिनियम के अन्तर्गत लाइसेंस धारियों को अतिरिक्त राशि एकत्रित करने हेतु अनुमति है। किन्तु इस अधिनियम में लाइसेंसधारी से केवल उनका अभिप्राय होगा जिन्हें विद्युत पारेषण और वितरण के लिए लाइसेंस प्राधिकारियों द्वारा दिया गया है। संबंधित प्राधिकारियों से इस पर समर्थन ले लेना, मेरी राय में काफी सहायक होगा।"

"यदि अनुमेय हो तो हम प्राधिकारियों से अनुमोदन प्राप्त कर सकते हैं जो बाद में कोई कठिनाई होने पर सहायक हो सकता है। सभी संभावनाओं में टीएमपी द्वारा बुलाई गई बैठक के दौरान विद्युत बोर्ड की ओर से प्रतिनिधित्व होगा। इस मुद्दे पर वही पर विचार-विमर्श हो सकता है।"

"जहाँ तक अन्य पत्तन उपयोगकर्ताओं के साथ, जो प्रधानतः समान हैं, किए गए अनुबंध की बात है, मुझे लगता है कि धारा (ii) आपकी मदद के लिए आयेगी। यह धारा विनिर्देश करती है कि लाइसेंसधारी पट्टे की अवधि के दौरान हस्तान्तरित भूखण्ड या उसके ऊपर निर्माण किए जाने वाले भवन के संबंध में सभी दरों, करों और प्रत्येक प्रकार के प्रभार का भुगतान करेगा जो आज देय है या आज के बाद पट्टादाता या पट्टाधारक द्वारा, देय हो जाएंगे। इस प्रावधान का अर्थ होगा कि कोई भी दरें कर या प्रभार, जो संशोधित हैं- संशोधित किए जा रहे हैं या संशोधित किए जाने हैं, पट्टाधारक द्वारा देय होंगे।"

"अनुबंध के इस विशेष कालम में, यह विशिष्ट रूप से लिखा हुआ है कि लाइसेंसों पर लगाए गए प्रभार टीएनईबी की अनुसूचित दरों के अनुसार होंगे। इसलिए मेरी राय में यदि अतिरिक्त वसूली के लिए कोई प्रयास किया जाता है तो मेसर्स पीएसए एसआईसीएल लिमि. निश्चित रूप से अपने अधिकारों को वैध सिद्ध कर सकता है, और अनुबंध की धारा 6.1.8 में प्रदत्त के अतिरिक्त वसूली के लिए कोई प्रयास किया जाता है तो उससे अधिक कुछ भुगतान नहीं करता।"

"मेरा यह सुझाव होगा कि प्रस्ताव को सभी उपयोगकर्ताओं के लिए, मेसर्स पीएसए एसआईसीएल लिमि. को छोड़कर जो अपने अनुबंध के द्वारा आपके साथ रक्षित है, लागू किया जा सकता है। वृद्धि की प्रतिशतता के बारे में मेरा अनुमान है कि इसे एक तर्क संगत अनुपात में होना चाहिए।

7. इस प्रकरण में परामर्श से संबंधित प्रक्रिया इस प्राधिकरण के कार्यालय में रिकार्ड पर उपलब्ध है। प्राप्त टिप्पणियों के सारांश और संबंधित पक्षों द्वारा दिए गए तर्क संबंधित पक्षों को अलग से भेजे जाएंगे। ये विवरण हमारे वेबसाइट www.tariff authority.org पर भी उपलब्ध हैं।

8. इस प्रकरण पर कार्रवाई के दौरान एकत्रित सूचनाओं की समग्रता के संदर्भ से निम्नलिखित स्थिति उभरती है :-

- (i) टीपीटी का प्रस्ताव अधिक्षेत्र के भौगोलिक क्षेत्र के भीतर विभिन्न प्रयोजनों से विद्युत के वितरण में सन्निहित उपरिव्यय खर्च की भरपाई के लिए नई प्रशुल्क मद आरम्भ करने के लिए है। यद्यपि पत्तन का लक्ष्य विद्युत के वितरण में लगी कम से कम प्रत्यक्ष लागत की वसूली करना है, इसने लेवी को 20% तक सीमित रखने का प्रस्ताव किया है क्योंकि वास्तविक लागत पर आधारित दर कथित रूप से बहुत अधिक है।
- (ii) इस समय पत्तन अपने उपयोगकर्ताओं से, तमिलनाडु विद्युत बोर्ड (टीएनईबी) को दिए जा रहे प्रशुल्क के अनुसार लागू दरें ही वसूलता है। जैसाकि पत्तन द्वारा सही-सही उल्लेख किया गया है, टीएनईबी को दिए जा रहे विद्युत प्रभारों के साथ-साथ उल्लेख किया गया है, यह अपने क्षेत्र के भीतर विद्युत के वितरण हेतु आवश्यक संरचना के निर्माण एवं अनुरक्षण पर धन खर्च करता है। वर्तमान व्यवस्था में संबंधित उपरिव्यय खर्चों को सामान्य प्रशासनिक उपरिव्यय के भाग के रूप में समझा जाता है, और विभिन्न गतिविधियों में समानुपातिक रूप से बांट दिया जाता है। इसका अर्थ हुआ कि टीपीटी द्वारा अनुरक्षित विद्युत संस्थापनाओं से संबंधित व्यय टीपीटी की सभी गतिविधियों के प्रशुल्क के ऊपर फैला दिया जाता है। इस प्राधिकरण का सदा यह मत रहा है कि प्रभारों की वसूली संवाओं / सुविधाओं के अनुपात में होनी चाहिए और इस प्रकार के प्रभार संबंधित उपयोगकर्ताओं से वसूल किए जाने चाहिए, न कि उनकी परेष्ठ वसूली की जाए। इस दृष्टिकोण से देखने पर टीपीटी द्वारा प्रस्तावित नजरिया इस प्राधिकरण की सामान्य विचारधारा के अनुरूप पाया गया है और उसे सैद्धांतिक रूप से समर्थन दिया जाना चाहिए। कुछ उपभोक्ता संगठनों द्वारा की गई टिप्पणियों के प्रत्युत्तर में टीपीटी ने स्पष्ट किया है कि उपयोगकर्ता, चाहे तो, सीधे तमिलनाडु विद्युत बोर्ड से विद्युत प्राप्त कर सकते हैं। तथापि यह तकनीकी संभाव्यता के अधीन होगी। इस बात को स्वीकार करना होगा कि जो संबंधित उपयोगकर्ता इस प्रकार की व्यवस्था के लिए इच्छा व्यक्त करेगा उसे इस व्यवस्था के लिए आवश्यक संस्थापनाओं के लिए निवेश करना होगा अथवा इस प्रकार की सुविधा के लिए विद्युत बोर्ड को भुगतान करना होगा।
- (iii) जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है और टीपीटी द्वारा स्वीकार किया जा चुका है कि टीपीटी के दरमान के पिछले सामान्य संशोधन के समय विद्युत आपूर्ति से संबंधित उपरिव्यय खर्चों को सामान्य प्रशासन व्यय का भाग समझा गया था। उपरिव्यय व्यय खर्चों की भरपाई के लिए अन्य प्रशुल्कों की पुनर्गणना के बिना इस मुकाम पर यदि कोई नई लेवी आरम्भ की जाती है तो निश्चित रूप से यह दोहरी गणना हो जाएगी। इस प्रकार की गणना का अन्य प्रशुल्क मदों पर प्रभाव बहुत थोड़ा या नगण्य हो सकता है और दोहरी गणना की अनुमति देने के लिए यह कोई वैधकारण नहीं हो सकता। यहाँ यह ध्यान देने योग्य है कि इस प्रकार के उपरिव्यय खर्चों को, इस प्राधिकरण द्वारा, अन्यत्र, दोहरी गणना की संभावना सगाप्त करने के लिए, नई प्रशुल्क मद का निर्धारण करते समय बाहर रखा गया था। ऐसा होते हुए, इस प्रकरण में यह उचित होगा कि टीपीटी के दरमान के अगले सामान्य संशोधन के समय, जो सितम्बर 2004 में अपेक्षित है, यदि अन्यथा ग्राह्य हो तो, प्रस्तावित लेवी आरम्भ कर दी जाए। इस प्रकार का प्रस्ताव तैयार करते समय टीपीटी, पत्तन द्वारा स्वयं उपयोग में लाई जाने वाली और अपनी आवासीय बस्ती में उपयोग की जाने वाली बिजली पर होने वाले व्यय की भरपाई के लिए उपयोगकर्ताओं से लेवी का भुगतान करने की अपेक्षा न करने का तृतीकोरिन चैम्बर ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्रीज के सुझाव पर भी विचार करें। इस प्रकार के व्यय को सामान्य प्रशासन उपरिव्यय ही समझा जा सकता है और उसे पत्तन की सभी गतिविधियों में समानुपातिक रूप से बांटा जा सकता है।
- (iv) तृतीकोरिन चैम्बर ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्री ने इस प्रकार का प्रभार लगाने हेतु टीपीटी की सक्षमता पर विद्युत अधिनियम 2003 के संदर्भ से एक सहत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है। जबकि यह प्राधिकरण टीपीटी के प्रस्ताव का सिद्धांत रूप में समर्थन करता है, विद्युत के वितरण के बारे में पत्तन की वित्तीय स्थिति को निस्संदिग्ध रूप से स्पष्ट करने की आवश्यकता है ताकि इस प्रकार की दरों को अनुमोदित करने की इस प्राधिकरण की सक्षमता स्थापित की जा सके। टीपीटी ने विद्युत अधिनियम 2003 के खंड 13 के प्रावधानों पर भरोसा किया है। इस अधिनियम के खंड 13 के अनुसार टीपीटी जैसे स्थानीय प्राधिकरण को, विद्युत के वितरण के लिए लाइसेंस की आवश्यकता से छूट प्राप्त है। इस विद्युत अधिनियम के खंड 13 को साक्ष्यानीपूर्वक पढ़ने से यह स्पष्ट होता है कि इस प्रकार की छूट अपने आप नहीं मिल जाती है, बल्कि समुचित सरकार की सिफारिश पर समुचित आयोग से इस आसय की एक अधिसूचना की आवश्यकता होती है। टीपीटी को छूट प्रदान करने वाला, किसी समुचित आयोग द्वारा जारी की गई कोई अधिसूचना रिकार्ड में नहीं है।

टीपीटी ने, इसके आगे, विद्युत अधिनियम 2003 के खंड 184 का संदर्भ दिया है जो यह अनुबंधित करता है कि इस अधिनियम के प्रावधान केन्द्र सरकार के रक्षा और परमाणु ऊर्जा से संबंधित मंत्रालयों, विभागों और ऐसे ही समान मंत्रालयों या विभागों या उपक्रमों या बोर्डों या ऐसे मंत्रालयों और विभागों के नियंत्रणधीन संस्थानों पर जिन्हें केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया हो, लागू नहीं होंगे। जब इन प्रावधानों की टीपीटी पर अनुप्रयोज्यता सिद्ध नहीं है, यह स्पष्ट नहीं है कि क्या केन्द्रीय सरकार से कोई औपचारिक अधिसूचना अपेक्षित होगी या नहीं। अपने दावे के समर्थन में टीपीटी द्वारा प्रस्तुत की गई कानूनी सलाह निष्कर्षी नहीं है।

- (v) टीपीटी द्वारा प्रस्तुत की गई कानूनी सलाह यह सुझाव देती है कि लाइसेंसधारकों को अतिरिक्त राशि एकत्रित करने की अनुमति है, जो वास्तव में टीपीटी का प्रस्ताव ही है। तथापि कानूनी राय, यह उल्लेख करते हुए कि विद्युत अधिनियम के अनुसार लाइसेंस धारक से अभिप्राय केवल उनसे होगा जिन्हें पारेषण और वितरण के लिए प्राधिकारियों द्वारा लाइसेंस दिए गए हैं। अपने प्रस्ताव के समर्थन में, टीपीटी ने, टीएनईबी द्वारा जारी की गई विद्युत आपूर्ति की शर्तों और निबन्धनों के संबंधित अंशों की प्रति भेजी है। इस दस्तावेज की धारा 31.03(ii) स्पष्टतौर पर हानि-लाभ रहित आधार पर, उपयोग की लागत वसूलने की अनुमति प्रदान करती है। तथापि यह प्रावधान कथित रूप से वाणिज्यिक या कार्यालय या आवासीय परिसरों के मामले में लागू है जहाँ हाई टेंशन या लो टेंशन विद्युत आपूर्ति मूलरूप से परिसर के निर्माता या प्रोन्नतकर्ता के नाम प्राप्त की जाती है जो बाद में परिसर का स्वामित्व या तो सम्पूर्ण रूप से विभिन्न व्यक्तियों को हस्तांतरित कर देता है या आंशिक रूप से विभिन्न व्यक्तियों को सौंप देता है और शेष पट्टे के लिए रख लेता है। यह बहुत स्पष्ट नहीं है कि क्या पत्तन न्यास इस परिमाण में खरा उतरता है। टीपीटी का प्रस्ताव टीएनईबी की टिप्पणियों के लिए उन्हे भेजा गया था। किन्तु हमें उनसे कोई प्रत्युत्तर नहीं मिला है।

- (vi) टीपीटी ने पीएसए एसआईसीएल को भी प्रस्तावित लेवी की पट्टी में समेटने का प्रस्ताव किया है। पीएसए एसआईसीएल और टीपीटी के बीच लेन-देन एक विशिष्ट बीओटी लाइसेंस अनुबंध द्वारा संचालित होता है। पीएसए एसआईसीएल ने प्रस्तावित लेवी को इस दावे के साथ चुनौती दी है कि उसे, बीओटी अनुबंध के अनुसार, टीएनईबी की अनुसूचित दरों के आधार पर प्रमारों की प्रतिपूर्ति करनी पड़ेगी। बीओटी अनुबंध की धारा 61.8 विद्युत और जल आपूर्ति व्यवस्था को विनियमित करती है। संबंधित धारा स्पष्ट रूप से विनिर्देश करती है कि लाइसेंसधारक पर लगाए गए प्रमार टीएनईबी की अनुसूचित दरों के अनुसार होंगे। टीपीटी द्वारा प्राप्त की गई कानूनी राय में भी इसी स्थिति की पुष्टि की गई है। यह मानते हुए कि विद्युत आपूर्ति के लिए टीएनईबी द्वारा जारी की गई शर्तें और निबन्धन वैध हैं और इन शर्तों व निबन्धनों की धारा 31.03 टीपीटी के लिए प्रासंगिक होगी, यह स्पष्ट नहीं है कि क्या शब्द "टीएनईबी की अनुसूचित दर" में प्रस्तावित उपरिव्यय लेवी सम्मिलित होगी या नहीं। पुनश्च, इस मुद्दे को टीपीटी और टीएनईबी द्वारा स्पष्ट नहीं किया गया है।

- (vii) पिछले पैराग्राफों में जो कुछ बताया गया है, उसकी दृष्टि से, यह स्पष्ट होता है कि टीपीटी के प्रस्ताव को इस मुकाम पर दो कारणों से स्वीकार नहीं किया जा सकता। प्रथमतः उपरिव्ययों को दो बार गिना गया है। दूसरे, प्रस्तावित प्रशुल्क व्यवस्था को अनुमोदन प्रदान करने से पहले इस प्रकरण में उठने वाले कानूनी मुद्दों को वरीयता से सुलझा लिया जाए। पत्तन के विधिक सलाहकार ने सुझाव दिया है कि टीएनईबी की राय ले ली जाए। पत्तन इस दिशा में कार्यवाई कर भी ले तो भी हमें विश्वास नहीं है कि केवल इतना ही पर्याप्त होगा। पत्तन इस मुद्दे को तमिलनाडु विद्युत विनियामक आयोग को सौंप सकता है और इस मामले में सही कानूनी स्थिति पर उनका मार्गदर्शन प्राप्त कर सकता है। जैसाकि पहले ही उल्लेख किया जा चुका है कि इस प्राधिकरण की मनशा टीपीटी के दृष्टिकोण का सिद्धांततः समर्थन तो करना चाहता है किन्तु लेवी लगाने संबंधी विचार-विमर्श को टीपीटी के दरमान में अगले सामान्य संशोधन तक टालना चाहते हैं बशर्ते टीपीटी प्रस्ताव दोबारा प्रस्तुत करने से पहले कानूनी मुद्दों पर उपरोक्त ढंग से स्पष्टीकरण प्राप्त कर ले।

10. परिणामस्वरूप और ऊपर दिए गए कारणों से और समग्र विचार विमर्श के आधार पर, यह प्राधिकरण, विद्युत आपूर्ति से संबंधित उपरिव्यय खर्चों की भरपाई के लिए इस मुकाम पर नई लेवी लगाने के बारे में टीपीटी के प्रस्ताव को अस्वीकार करती है। विभिन्न कानूनी मुद्दों पर स्पष्टीकरण के अधीन, टीपीटी को, फिर भी सलाह दी जाती है कि वह प्रस्तावित लेवी को, अपने दरमान के अगले सामान्य संशोधन जो सितम्बर 2004 में अपेक्षित है, से संबंधित प्रस्ताव का भाग बना ले।

अ.ल. बोंगिरवार, अध्यक्ष

[विज्ञापन/III/IV/143/04/असा.]

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

NOTIFICATION

Mumbai, the 19th May, 2004

No. TAMP/79/2003-TPT.—In exercise of the powers conferred by Sections 49 and 50 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby disposes of the proposal received from the Tuticorin Port Trust (TPT) for fixing a levy to recover overhead charges in respect of electricity charges as in the Order appended hereto.

No. TAMP/79/2003-TPT.

The Tuticorin Port Trust (TPT)

Applicant

ORDER

(Passed on this 4th day of May 2004)

This case relates to a proposal received from the Tuticorin Port Trust (TPT) for fixing a levy to recover overhead charges in respect of electricity charges.

2.1. The TPT has made the following main points in its proposal:

- (i). The charges in respect of electricity consumed by the consumers/ users is collected as per the tariff prescribed by the Tamil Nadu Electricity Board (TNEB).

In case of PSA SICAL, a separate transformer exists, hence in addition to consumption charges, Maximum Demand charges and meter rent are also collected from PSA SICAL.

- (ii). While distributing the electricity to the consumers, the port incurs heavy expenditure on Maximum Demand Charges, infrastructure provided for distribution, distribution loss and operation and maintenance cost. Hence, it is proposed to recover overhead charges from the users. Since the rate worked out by the port in June 2003 to recover the overhead charge was not acceptable to the members of its Board of Trustees, a three member Committee was constituted to recommend the levy to be recovered as overhead charge in respect of the electricity consumed by users.

- (iii). As per the cost calculation submitted by the Committee, 142.77 % is to be recovered from the PSA SICAL and 158.09% is to be levied on the electricity charges from other users to recover the total overhead charge. In this context, it has quoted that the electricity overhead charge levied by the COPT is at 291% and at the Jawaharlal Nehru Port Trust it is at 20%.

- (iv). In view of the huge indirect cost involved, the Committee subsequently proposed to recover only the direct fixed cost @ 52.55% from port users and 33.62% from the PSA SICAL.

- (v). Two members of the Committee objected to this reduced rate also and suggested to recover a levy at a nominal rate of 5%. The members of the Committee pointed out that the users would like to avail power supply directly from the Tamil Nadu Electricity Board after obtaining No objection Certificate from the port.

2.2. The Board of Trustees of TPT has finally approved recovery of overhead charge @ 20% of the electricity bill from the port users, contractors, etc., on an adhoc basis. The port has stated that the proposed levy would be reviewed later.

3.1. In accordance with the consultative procedure adopted, a copy of the proposal was forwarded to the concerned user organisations for their comments.

3.2. The comments received from the above users were forwarded to the TPT as feedback information. In response, the TPT has furnished its comments as summarised below:

- (i). As per the lease agreement executed with the TPT, the Tuticorin Steamer Agents' Association (TSAA) have to bear the tariff fixed by the port from time to time. Copy of the Agreement has been attached in support of its claim.

- (ii). As regards the observation of the TSAA that port has not furnished proper justification, it has clarified the port also incurs repairs and maintenance (which includes the establishment charges of the staff deployed) and depreciation cost on the electrical installation, in addition to the tariff paid to the TNEB. This has to be recovered from the users availing the facility.
- (iii). It has referred to various clauses of the Electricity Act, 2003 as reproduced below to clarify the legal provisions of the proposed levy:

Part - IV - Licensing

Section No.13 – Power to exempt

“ The Appropriate Commission may on the recommendations of the Appropriate Government, in accordance with the national policy formulated under section 5 and in public interest direct by notification that subject to such conditions and restrictions, if any, and for such period or periods, as may be specified in the notification, the provisions of section 12 shall not apply to any local authority, Panchayat Institution, users’ association, co-operative societies, non-governmental organisations or franchisees.”

Section No.41

“ “Local authority” means any Nagar Panchayat, Municipal Council, Municipal corporation, panchayat constituted at the village, intermediate and district levels, body or port commissioners or other authority legally entitled to or entrusted by the Union or any State Government with, the control or management of any area or local fund”

Section No.184

“ The provisions of this Act shall not apply to the Ministry or Department of the Central Government dealing with Defence, Atomic Energy or such other similar Ministries or Departments or undertakings or Boards or institutions under the control of such Ministries or Departments as may be notified by the Central Government”

As per the above provisions in the Electricity Act 2003, it is clear that the provision of obtaining license to be an authorized person to transmit, distribute the electricity, etc., shall not apply to any “Local authority” and the definition of the term “Local Authority” includes port commissioners apart from the other bodies.

- (iv). Further, it has also referred to the Terms and Conditions of Electricity Supply entered with the TNEB in support of its claim. Clause 31.03 (1)& (2) in this document reads as follows:

“The builder or promoter of the complex in whose name the supply continues, may be permitted to extend power supply to the individual owners of the flats etc. or to the lessees by installing sub-meters and to collect the cost of consumption of power from them on no profit or no loss basis (i.e. sharing of expenses of consumption of Electricity) and this shall not be treated as unauthorised extension of supply or sale of energy.”

The port is extending supply of power to users. As per this clause, the port can collect charges towards recovery of the expenditure incurred over and above the amount payable for consumption of electricity on no loss and no gain basis.

- (v). Maximum demand charge is continuously increasing and there has been substantial increase in maintenance and establishment charges also. The gap

between tariff of HT and LT has also narrowed down. Apart from these factors, the port also incurs huge capital expenditure for strengthening the electrical installations. While the nature of expenditure may be the same, the different types of expenditure and quantum of expenditure do not remain the same. Hence it is proposed to introduce this overhead charges.

- (vi). The users have option to avail power directly from the TNEB.
- (vii). The Electricity Act provides for fixed charges in addition to charges for actual electricity supplied, therefore, the proposal submitted by the port and being considered by the Authority is in order.
- (viii). The issue about monitoring port's own private consumption are outside the purview of the current proposal.
- (ix). While the port is paying the charges for electricity to TNEB at the rates applicable to HT (III) (commercial) consumers, the collections from the consumers by the port are on the basis of LT (V) commercial rates. In addition, the port has to meet the maximum demand charges and other incidental charges of maintenance, etc. Hence, comparison of the tariff levied by the port and the TNEB tariff for electricity charges is not relevant.
- (x). The PSA SICAL have to pay the electricity charges as per the TNEB tariff and the TNEB tariff provides for collection of cost on no profit no loss basis. Hence, the PSA SICAL should also pay the proposed overhead charge.

4. Based on a preliminary scrutiny of the proposal, the TPT was requested to furnish additional information on various points. The TPT has furnished clarifications with reference to the legal provisions of the proposed levy as mentioned earlier. In addition to that, the TPT has stated the following main points:

- (i). The electricity cost has been charged to various sub-activities as per the units consumed; and, the related overhead expenses are treated as part of management and general administration expenditure and apportioned to the various sub-activities in the cost statements furnished at the time of the last general revision proposal.
- (ii). The current proposal is subsequent to the submission of the general revision proposal, therefore, the issue of exclusion of this cost element from the general revision proposal does not arise. The total collection from users from the instant proposal comes to Rs.47.57 lakhs and the impact of this on the general revision proposal will be almost nil and hence the same is not a relevant factor for the current proposal.
- (iii). The unit rate of electricity levied by the TNEB is Rs.5/- as per HT tariff and the effective rate works out to Rs.6.20 per unit after including the maximum demand charges of Rs.300/- per KVA per month and the meter rent. However, the port collects LT tariff fixed by the TNEB (i.e. Rs.5.30 for first 200 unit, Rs.5.80 above 200 unit plus 5% E. Tax and fixed charges of Rs.60/-) without recovery of any overhead charge.
- (iv). It has confirmed that the cost attributable to consumption by the port, port employees, and the PSA SICAL have already been excluded in this computation.

5. A joint hearing in this case was held on 19 February 2004 at the TPT premises. At the joint hearing, the TPT and the concerned users have made their submissions.

6.1. As decided in the joint hearing, the TPT was requested to forward copy of the legal opinion obtained by it on the competence of the port to levy the proposed overhead

charge vis-à-vis the provisions in the Electricity Act, 2003 and to furnish relevant cost statements for the years 2003-04 (RE) and 2004-05 (BE).

6.2. The TPT has furnished the requisite cost statements and a copy of the legal opinion obtained by it on the competence of the port to levy the proposed overhead charge. Some of the main observations made by the legal advisor of the TPT are reproduced below:

"I would also suggest that you 'd better collect an opinion from T.N.E.B. authorities on the issue of collection of service charges. I guess under the Electricity Act, the licencees are allowed to collect an extra sum. But the licencees in the Act would mean only those who are given licence by the Authorities for transmitting and distributing. It would be helpful, in my opinion, to have an endorsement from the concerned authorities."

"If permissible, we can get an approval from the Authorities, which would be conducive in case of any predicament lateron. In all possibilities there would be representation from the electricity board during the meeting convened by TAMP. This issue could discussed thereitself."

"As far as the agreement entered in to with other port users, which are predominantly uniform, I find that clause (ii) would come into your rescue. This clause specifies that the licensee shall, during the period of lease pay all rates, taxes and charges of every description now payable or hereafter becomes payable by the lesser or lessee in respect of the demised plot of plot or the buildings to be erected thereupon. This provision would mean that any rates, taxes or charges revised, being revised or to be revised shall also be paid by the lessee."

"In this particular column in the agreement, it is specifically mentioned that the 'charges' levied on the licenses shall be as per the schedule rates of T.N.E.B. Therefore in my opinion M/S PSA SICAL Ltd. can definitely vindicate their rights in case of any attempt for additional collection and not to pay anything extra other than what is granted in the agreement in the clause 6.1.8."

"I would suggest that the proposal could be implemented with a proportionate hike, to all the users, except M/S PSA SICAL Ltd, who is protected by their agreement with you. Speaking about the percentage of hike, I guess, it has to be in the reasonable ratio."

7. The proceedings relating to consultation in this case are available on records at the office of this Authority. An excerpt of the comments received and arguments made by the concerned parties will be sent separately to the relevant parties. These details are also available at our website www.tariffauthority.org.

8. With reference to the totality of information collected during the processing of this case, the following position emerges:

- (i). The proposal of TPT is for introduction of a new tariff item to cover the overhead expenses involved in distribution of electricity for various purposes within its geographical area of jurisdiction. Although the objective of the port is to recover at least the direct cost incurred in distribution of electricity, it has proposed to restrict the levy at 20% since actual cost based rate is reportedly very high.
- (ii). Presently, the port recovers from its users the tariff being paid to the Tamilnadu Electricity Board (TNEB) at the applicable rates. As correctly pointed out by the port, in addition to payment of electricity charges to the TNEB, it also incurs expenditure on creation and maintenance of the required infrastructure for distribution of electricity within its area. In the existing arrangement the related overhead expenses are treated as part of the general administrative overheads

and apportioned to the various activities. This means the expenditure relating to the electrical installations maintained by the TPT is spread over the tariff for all the activities of the TPT. This Authority has always held that recovery of charges should commensurate with the services / facilities provided and such charges are to be recovered from the concerned users instead of resorting to indirect recovery. Viewed from this perspective, the approach proposed by the TPT is found to be in line with the general thinking of this Authority and deserves to be endorsed in principle. In response to the comments made by some of the user organizations, the TPT has clarified that the users have an option to avail power directly from Tamil Nadu Electricity Board. This will, however, be subject to technical feasibility. It has to be recognized that the concerned users opting for such an arrangement would have to necessarily invest in the required installations or pay the Electricity Board for creation of such facility.

- (iii). As mentioned above and conceded by the TPT, the overhead expenses related to electric supply were treated as part of general administration expenditure at the time of the last general revision of Scale of Rates of TPT. If a separate levy to recover the overhead expenses is introduced at this juncture without reworking other tariff, it will definitely be a double counting. The impact of such a review on other tariff item could only be marginal or negligible cannot be a valid reason for allowing double counting of overheads. It is noteworthy that such overhead expenses are excluded by this Authority while fixing new tariff items elsewhere in order to remove the possibility of double counting. That being so, it will be appropriate in this case to introduce the proposed levy, if otherwise admissible, at the time of the next general revision of Scale of Rates of TPT which is due in September 2004. While preparing such a proposal, TPT may consider the suggestion made by the Tuticorin Chamber of Commerce and Industry about not requiring the users to pay the levy on the expenditure incurred for the electricity consumed by the port for its own use and for residential colony. Such expenditure can continue to be treated as general administrative overheads and apportioned to all the activities of the Port.

- (iv). The Tuticorin Chamber of Commerce and Industry has raised an important issue about the competence of the TPT to levy such a charge with reference to the provisions in the Electricity Act, 2003. While this Authority endorses in principle the proposal of TPT, the legal position of the port in relation to distribution of electricity needs to be clarified unambiguously so that the competence of this Authority to approve such rate can be established. The TPT has relied on the provisions of Section 13 of the Electricity Act 2003 which exempts a local authority like TPT from the requirement of having a license for distribution of electricity. A careful reading of Section 13 of the Electricity Act reveals that such an exemption is not automatic but, requires a notification to that effect from the Appropriate Commission on the recommendations of the Appropriate Government. No such notification issued by the Appropriate Commission exempting TPT is available on record.

The TPT has further referred to Section 184 of the Electricity Act 2003 which stipulates that the provisions of the Act shall not apply to the Ministry or Department of Central Government dealing with defence, atomic energy or such other similar Ministries or departments or undertakings or Boards or institutions under the control of such Ministries or departments as may be notified by the Central Government. While applicability of this provisions to TPT is not in doubt, it is not clear whether any formal notification to this effect would be required from the Central Government. The legal advice furnished by the TPT in support of its contention is not conclusive.

- (v). The legal advice submitted by the TPT suggests that the licensees are allowed to collect an extra sum which, in fact, is the proposal of the TPT. The legal

opinion, however, qualifies this position by mentioning that the licensee as per the Electricity Act will mean only those who are given license by the Authorities for transmitting and distribution. In support of its proposal, the TPT has forwarded a copy of the relevant portion of the terms and conditions of electric supply issued by the TNEB. Clause 31.03 (i) of this document clearly permits collection of cost of consumption on no profit or not loss basis. This provisions is, however, stated to be applicable in case of commercial or office or residential complexes where high tension or low tension power supply is availed originally in the name of builder or promoter of the complex who subsequently transfers ownership of the complex either entirely to different individuals or partly to different individuals retaining the balance for lease. It is not very clear whether the Port Trust will fit into this definition. The proposal of TPT was forwarded to the TNEB for their comments, but we have not received any response from them.

(vi). The TPT has proposed to cover the PSA SICAL also within the ambit of the proposed levy. The transactions between PSA SICAL and TPT are governed by a specific BOT license agreement. The PSA SICAL has challenged the proposed levy claiming that it has to reimburse charges based on the scheduled rates of TNEB as per the BOT agreement. Clause 6.1.8 of the BOT agreement regulates power and water supply arrangement. The relevant clause clearly specifies that that charges levied on the licensee shall be as per the scheduled rate of the TNEB. The legal opinion obtained by TPT also endorses this position. Presuming that the terms and conditions of supply of electricity issued by the TNEB is valid and clause 31.03 of such terms and conditions will be relevant to TPT, it is not clear whether the term 'scheduled rate of TNEB' will include the proposed overhead levy. Again, this issue is not clarified by the TPT and the TNEB.

(vii). In view of what has been explained in the preceding paragraphs, it becomes clear that the proposal of TPT cannot be approved at this juncture for two reasons. Firstly, the overheads are counted twice. Secondly, the legal issues arising in this case need to be frontally addressed before approving the tariff arrangement proposed. The legal advisor of the port has suggested to obtain an opinion from TNEB. While the port may take necessary action in that direction, we are not sure whether this alone would be sufficient. The Port may also refer the issue to the Tamil Nadu Electricity Regulatory Commission and obtain their guidance on the correct legal position in this matter. As mentioned earlier, this Authority is inclined to endorse the approach of TPT in principle but defer consideration of introduction of levy till the next general revision of Scale of Rates of the TPT subject to the legal issues getting clarified in the manner mentioned above by TPT before they resubmit the proposal.

9. In the result, and for the reasons given above, and based on a collective application of mind, this Authority rejects the proposal of the TPT for introduction of a new levy to cover overhead expenses relevant to electric supply at this juncture. Subject to clarifications on the various legal issues, the TPT is, however, advised to include the proposed levy as a part of its proposal for the next general revision of its Scale of Rates which is due in September 2004.

A.L. BONGIRWAR, Chairman

[Advt./III/IV/143/04 Exty.]